



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092023-248851  
CG-DL-E-20092023-248851

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]  
No. 227]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2023/भाद्र 29, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023/BHADRA 29, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
जांच शुरूआत अधिसूचना  
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: (एसएसआर - 06/2023)

**विषय- चीन जन.गण. से "सोलर मॉड्यूल के लिए एथीलिन विनायल एसीटेट (ईवीए) शीट" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।**

फा. सं. 07/12/2023-डीजीटीआर.—1. समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, मै. रिन्यूशिस इंडिया प्रा.लि.(जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से

निर्यातित “सोलर माँड्यूल के लिए एथीलीन विनायल एसिटेट (ईवीए) शीट” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच करने का अनुरोध किया गया है।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण., मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया तथा थाइलैंड के खिलाफ मूल जांच की शुरुआत अधिसूचना सं. 06/9/2018-डीजीएडी, दिनांक 04.04.2018 के माध्यम से शुरू की गई थी। तथापि यह जानने के बाद के बाद कि दक्षिण कोरिया से आयात की मात्रा न्यूनतम सीमा से कम थी, चीन जन.गण., मलेशिया, सऊदी अरब और थाइलैंड से आयातों के विरुद्ध अंतिम जांच परिणाम सं. 06/9/2018-डीजीएडी दिनांक 21.02.2019 के माध्यम से शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। ये शुल्क सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 29.3.2019 के माध्यम से लगाए गए थे। घरेलू उद्योग ने केवल चीन जन.गण. के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए आवेदन दायर किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जांच की अवधि में सऊदी अरब, थाइलैंड और मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है।
3. अधिनियम की धारा 9 क, (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो उसे लगाने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है। प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन है उत्पाद वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित था, जो निम्नानुसार है :  
*“सोलर माँड्यूल के लिए एथिलीन विनाइल एसिटेट (ईवीए) शीट”। यह सोलर पीवी (फोटो वोल्टेक) माँड्यूल के विनिर्माण में प्रयुक्त पॉलिमर आधारित घटक है। ईवीए शीट का प्रयोग एग्जेशन और कुशनिंग कार्यों के निष्पादन हेतु सौर पीवी सेलों के एनकेप्सुलेशन के लिए किया जाता है। यह एक सर्वाधिक अनिवार्य घटक है जो ग्लास, सेल और बैकशीट को जोड़े रखता है और उसके प्रयोग काल के दौरान माँड्यूल को यांत्रिक रूप से सहारा देता है।*
5. ईवीए शीट एक्सट्रूजन तकनीक के प्रयोग से निर्मित प्लास्टिक शीट और फिल्मों की श्रेणी में आती है। यह एक पॉलीएथिलीन का कोपॉलीमर थर्मोप्लास्टिक मैटीरियल है जिसे मुख्यतः ट्यूबलर या ऑटो फ्लेव प्रक्रिया के प्रयोग से पॉलीमराइज किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को आम तौर पर एच एस कोड 3901 30, 3920 10, 3920 62, 3920 99 तथा 3921 90 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। तथापि, आयात अन्य एच एस कोडों के अंतर्गत ही हो रहे हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि एच एस कोड केवल सांकेतिक हैं और सभी स्थितियों में उत्पाद का विवरण लागू होगा।
6. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पहले की गई गई जांच में यथापरिभाषित के समान रहेगा।

#### ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु हैं। वर्तमान आवेदन मूल शुल्क का समय बढ़ाने के लिए समीक्षा के लिए है और चूंकि वर्तमान और

मूल जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद समान है, इसलिए प्रथमदृष्टया यह माना गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु “समान वस्तु” हैं।

#### ग. संबद्ध देश

8. मूल जांच में शुल्क चीन, मलेशिया, थाइलैंड तथा सऊदी अरब से आयातों के विरुद्ध लगाए गए थे। तथापि वर्तमान आवेदन केवल चीन से आयातों के विरुद्ध शुल्क को जारी रखने/विस्तार के लिए किया गया है। इस प्रकार वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश चीन जन.जन.गण. है।

#### घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह याचिका मै. रीनिवसिस रेनेवेबल प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और मै. विशाखा रेनेवेबल्स प्रा. लि., नवीटास एल्फा रेनेवेबल प्रा. लिमिटेड, अलीशान ग्रीम एनर्जी प्रा.लि., इनरलाइट सोलर फिल्म्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, फिल्मटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड, पिक्सोन ग्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और ईसीएपी ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है। आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का “एक प्रमुख हिस्सा” बनता है। इसके अलावा, आवेदक और समर्थकों के उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में काफी अधिक हिस्सा बनता है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो पीयूसी का आयात किया है और न ही चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु से किसी आयातक से संबंधित है। उपरोक्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदकन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

#### ड. पाटन के जारी रहने और पुनरावृत्ति की संभावना

##### i. सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक ने बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
11. प्राधिकारी ने इस जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य पर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के बाद विचार किया है।

##### ii. निर्यात कीमत

12. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत गौण स्रोत से तथा उनकी बाजार आसूचना से लिए गए आंकड़ों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा परिकलित की गई है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विचार किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

##### iii. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन का पाटन किया जा रहा है।

**च. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होनेकी संभावना**

14. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है।
15. आयात की मात्रा और मूल्य, संबद्ध देश से आयात कीमत, सकारात्मक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, घरेलू उद्योग के निष्पादन जो काफी घट गया है, चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध भारी क्षमताओं, चीन के उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार, भारतीय उद्योग की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रथम दृष्टया पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना दर्शाती है।

**छ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत**

16. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से सांख्यिकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

**ज. जांच की अवधि**

17. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21 और 2021-22 तथा जांच की अवधि शामिल होगी। पाटन और क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की जा सकती है।

**झ. प्रक्रिया**

18. वर्तमान समीक्षा जांच में अधिसूचना सं. 6/9/2018-डीजीएडी, दिनांक 21 फरवरी, 2019 के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं। प्राधिकारी पाटन और क्षति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।
19. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

**ञ. सूचना प्रस्तुत करना**

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों [dd15-dgtr@gov.in.](mailto:dd15-dgtr@gov.in), [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in) [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) तथा [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना जांच शुरुआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरुआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

#### ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ए डी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों [dd15-dgtr@gov.in.](mailto:dd15-dgtr@gov.in.), [jd13-dgtr@gov.in.](mailto:jd13-dgtr@gov.in.), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) और [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और ए डी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।
27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

#### ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. ऐसे अनुरोधों में प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी ऐसे अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के आधार पर इस आशय के कारणों का एक पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।
32. गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और उचित कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

#### ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

33. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें।

**ढ. असहयोग**

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2023

**Case No. AD (SSR) –06/2023**

**Subject: Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of “Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module” from China PR.**

**F. No. 7/12/2023-DGTR.—1.** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “Anti-Dumping Rules”), M/s RenewSys India Pvt. Ltd. (hereinafter referred to the “applicant” or the “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), for a sunset review investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of “Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module” (hereinafter referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

- 2 The original investigation was initiated by the Designated Authority vide initiation notification F. No.06/9/2018-DGAD, dated 04.04.2018 against China PR, Malaysia, Saudi Arabia, South Korea and Thailand. However, after finding that the import quantity from South Korea was negligible, the imposition of duty was recommended against the imports from China PR, Malaysia, Saudi Arabia, and Thailand vide final findings F. No.06/9/2018-DGAD dated 21.02.2019. The duties were imposed vide Customs Notification No. 15/2019 – Customs (ADD) dated 29.03.2019. The domestic industry has filed the application for continued imposition of anti-dumping duties against China PR only. This is because there have been no imports of the subject goods from Saudi Arabia, Thailand and Malaysia in the period of investigation.
- 3 In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. The Authority is required to review whether the expiry of the duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

- 4 The product under consideration in the present investigation is the same as defined in the original investigation which is as follows:

*“Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module”. It is the polymer based component used in the manufacturing of solar PV (Photo Voltaic) modules. EVA sheet is used for encapsulation of solar PV cells performing adhesion and cushioning functions. This is one of the most essential component which keeps glass, cell and backsheet integrated and support the module mechanically during its service life time.”*

- 5 The EVA sheet falls in the category of plastic sheets and films made using extrusion technology. It is a thermoplastic material, a copolymer of Polyethylene, polymerized using a tubular or autoclave process mainly. The product under consideration is generally imported under HS codes 3901 30, 3920 10, 3920 62, 3920 99 and 3921 90. However, imports are also taking place under other HS codes, therefore, it is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

- 6 The present investigation being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation.

## **B. LIKE ARTICLE**

- 7 The applicant has claimed that there is no difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The Authority in the previous investigation held that the products being manufactured by the domestic industry is like article to the product being imported into India from the subject country. The present application is for review of the extension of original duty and since the product under consideration for the present and original investigation is the same, it is *prima facie* considered that the subject good produced by the domestic industry and the subject good imported from the subject country are "like article".

## **C. SUBJECT COUNTRY**

- 8 In the original investigation, the duties were imposed against the imports from China, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia. However, the present application for continuation/extension of the duties is only filed against dumped imports from China PR. Thus, the subject country for the purpose of the present review is China PR.

## **D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

- 9 The application has been filed by M/s RenewSys Renewable Pvt. Ltd. and supported by M/s Vishakha Renewables Pvt. Ltd., Navitas Alpha Renewables Pvt. Ltd., Alishan Greem Energy Pvt. Ltd., Enerlite Solar Films India Private Limited, Filmtec Solar Private Limited, Pixon Greem Energy Private Limited, and ECAP Greentec Pvt. Ltd. The production of the applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production. In addition, the production of the applicant and supporters have a significant majority in total Indian production. The applicant has certified that it has neither imported the PUC nor is related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR or any importer of the subject goods in India. In view of the above and after examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

## **E. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING**

### **i. Normal Value**

- 10 The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 of Annexure I to the Rules.
- 11 The Authority has, for the purpose of this initiation, considered the normal value for China PR based on the cost of production of the domestic industry and after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

### **ii. Export price**

- 12 The export price for the subject goods from the subject country is calculated by the petitioner based on the data sourced from secondary source as well as their market intelligence. However, the Authority has considered DGCI&S data for the purpose of present initiation. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

### **iii. Dumping margin**

- 13 The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

**F. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY**

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry.
15. There is *prima facie* evidence of the likelihood of continuation of dumping and consequent injury in the event of cessation of duty, considering the volume and value of import, import price from the subject country, positive dumping margin and injury margin, performance of the domestic industry which has deteriorated, significant capacities available with the Chinese producers, capacity expansion by the Chinese producers, vulnerability of the Indian industry. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows the likelihood of dumping and injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

**G. INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION**

16. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry and having satisfied itself, on the basis of the evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**H. PERIOD OF INVESTIGATION**

17. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from April 2022 to March 2023 (12 months). The injury investigation period will cover the periods 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation. The data beyond the period of investigation may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

**I. PROCEDURE**

18. The present review investigation covers all aspects of the final findings published vide Notification No. 6/9/2018-DGAD, dated 21<sup>st</sup> February 2019. The Authority will also undertake a likelihood analysis of dumping and injury.
19. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**J. SUBMISSION OF INFORMATION**

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in), [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), and [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in). It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS-Excel format.
21. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed in this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
22. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit mentioned in this initiation notification.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**K. TIME LIMIT**

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses: [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in), [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), and [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.



26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### **L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
29. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate good cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

#### **M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

33. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

#### **N. NON-COOPERATION**

34. In case where an interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority